भारतीय कानून की रिपोर्ट

पुनरीक्षण **सिविल**

माननीय न्यायमूर्ति सी. जी. सूरी के समक्ष

मनोहर लाल - याचिकाकर्ता।

बनाम

साधु राम—उत्तरदाता।

1969 की सिविल पुनरीक्षण संख्या 646

1 अप्रैल, 1970।

पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (1949 का III) - धारा 13 और 1 5 (5) - संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम (1882 का IV) - धारा 106 और 116 - धारा 13 के तहत निष्कासन आवेदन दायर करने से पहले संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में किरायेदारी की समाप्ति की सूचना किराया प्रतिबंध अधिनियम के तहत - कब आवश्यक होती है- पट्टे का निर्धारण करने का इरादा दिखाने वाले मकान मालिक की ओर से प्रत्यक्ष कार्य का अभाव - पट्टे के निर्वाह के बारे में अनुमान - क्या तैयार किया जा सकता है - नोटिस की कमी की दलील - क्या अपीलीय स्तर पर उठाई जा सकती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में नोटिस देने का प्रश्न केवल तभी उठता है जहां उस धारा के प्रावधान या सिद्धांत लागू होते हैं या संविदात्मक किरायेदारी या किरायेदारी जिसे धारा 116 के तहत अस्तित्व में माना जाता है वह मासिक है या ऐसी मासिक किरायेदारी अस्तित्व में है और समय की बर्बादी या जब्ती से या अधिनियम की धारा 106 के उचित और न्यायसंगत सिद्धांतों के तहत उचित नोटिस द्वारा निर्धारित होने से पहले ही समाप्त नहीं हुई है।जहां हालांकि संविदात्मक किरायेदारी पहले ही समाप्त हो चुकी है और किरायेदार को कानून द्वारा प्रदत्त अपरिवर्तनीयता का दर्जा देते हुए एक वैधानिक किरायेदारी के तहत कब्जा जारी है, तो अधिनियम की धारा 106 के तहत कोई नोटिस आवश्यक नहीं है।

(पैरा 5)

यह माना गया कि जहां अधिनियम की धारा 106 के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया है, मकान मालिक को पट्टे का निर्धारण करने के अपने स्पष्ट इरादे को दिखाने के लिए कुछ करना चाहिए। जब्ती या अस्वीकरण को लागू करने के लिए मकान मालिक के स्पष्ट या स्पष्ट इरादे को दर्शाने वाले किसी भी कार्य के अभाव में, मकान मालिक

द्वारा पट्टे की समाप्ति की छूट दी जा सकती है और पट्टे को निर्वाह के रूप में मानने के उसके इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है।

यह माना गया कि जब पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम की धारा 13 के तहत निष्कासन के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है और सभी संबंधित द्वारा यह समझा जाता है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में किरायेदारी की समाप्ति की सूचना आवश्यक नहीं है, तो आवेदन में कोई उल्लेख नहीं हो सकता है कि किरायेदार को ऐसा नोटिस दिया गया था। इसलिए किरायेदार के लिए याचिका को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए किरायेदार की ओर से कोई जानबूझकर और सचेत कार्य नहीं किया जाता है ताकि छूट दी जा सके। नोटिस की कमी की दलील को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उठाने की अनुमति दी जा सकती है, भले ही यह कहा जा सके कि यह कार्यवाही के देर से चरण में थी।

(पैरा 7)

पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम की धारा 15 (5) के तहत हिसार के अपीलीय प्राधिकारी *(*जिला न्यायाधीश*)* श्री एससी गोयल के 21 मार्च, 1969 के आदेश में पुनरीक्षण के लिए याचिका दायर की गई है, जिसमें भिवानी के किराया नियंत्रक श्री जेबी गर्ग के *22* जून*,* 1968 के आदेश को उलट दिया गया है, जिसमें प्रतिवादी मनोहर लाल के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

प्रीतम सिंह जैन और वी० एम० जैन, याचिकाकर्ता की ओर से।

एच०एल सरीन और एच० एस० अवस्थी,अधिवक्ता,उत्तरदाताओं के लिए।

प्रलय

1. सी. जी. सूरी, जे०— यह पुनरीक्षण याचिका एक मकान मालिक द्वारा पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 की संख्या 3 (इसके बाद संक्षेप में 'किराया अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 15 (5) के तहत अपीलीय प्राधिकरण, हिसार के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी-किरायेदार को अपीलीय स्तर पर पहली बार आपत्ति उठाने की अनुमति दी गई है कि याचिकाकर्ता मकान मालिक संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की संख्या 4 की धारा 106 के संदर्भ में किरायेदारी की समाप्ति का नोटिस देने में विफल रहा था।अपीलीय प्राधिकारी, इस न्यायालय के हाल ही के पूर्ण पीठ के निर्णय **भैया राम बनाम महावीर प्रसाद (1)**[1] पर भरोसा करते हुए प्रतिवादी-किरायेदार की इस आपत्ति को बरकरार रखा और किराया अधिनियम की धारा 13 (2) (i) के तहत याचिकाकर्ता-मकान मालिक के आवेदन पर किराए का भुगतान न करने के आधार पर किराया नियंत्रक द्वारा दिए गए निष्कासन के आदेश को रद्द करने की उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। इसलिए याचिकाकर्ता-मकान मालिक द्वारा दायर निष्कासन आवेदन को

[1] आइ०एल०आर(1969) आइ पंजाब व हरियाणा 132= 1968 पी०एल०आर 1011

अपीलीय प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है व पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

2. मकान मालिक द्वारा बेदखली आवेदन दाखिल करने से पहले किरायेदार पर बेदखली के नोटिस की सेवा के विषय पर केस कानून में हाल ही में बदलाव हुए हैं और जब किराया नियंत्रक के समक्ष पार्टियों द्वारा याचिका दायर की गई थी तो स्थिति बहुत अलग थी जिसके परिणामस्वरूप इन दलीलों को कानून की वर्तमान स्थिति के अनुरूप तैयार नहीं किया गया था जैसा कि स्वराज पाल बनाम जनक राज *(2)* और भैया राम बनाम महावीर पार्षद *(1)* में इस न्यायालय के दो बेंच के फैसलों के बाद सामने आया है। राज कुमार बनाम मेजर गुरमीतिंदेर सिंह (3) व जगजीत राय शर्मा बनाम बिहारी लाल गुलियानी (4) में एकल पीठ के दो निर्णयों में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया गया था लेकिन सवराज पाल के मामले (2) और भैया राम के मामले (1) में पीठ के फैसले पर उसी न्यायाधीश ने बाद में श्रीमती गार्गी देवी बनाम बिहार मामले में भरोसा किया।राज कुमार (3) और स्वराज पाल (2) के मामलों में निर्णय लगभग एक ही महीने के दौरान दिए गए थे और इनमें से किसी भी मामले पर दूसरे में ध्यान नहीं दिया जा सकता था, लेकिन भैया राम के मामले (1) में पूर्ण पीठ के फैसले को माननीय न्यायाधीश के ध्यान में लाया गया था जब उन्होंने जगजीत राय शर्मा के मामले (4) का फैसला किया था और उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि राज कुमार के मामले (3) में उनके फैसले को भैया राम के मामले (1) में पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था, और इसलिए अपीलीय प्राधिकरण ने किरायेदार के अनुरोध को अपीलीय स्तर पर लिखित बयान में संशोधन करने के लिए सही तरीके से अस्वीकार कर दिया था ताकि किरायेदार के खिलाफ निष्कासन आवेदन दायर करने से पहले मकान मालिक द्वारा निष्कासन के नोटिस की अनुपस्थिति के बारे में आपत्ति उठाई जा सके। पट्टाधारी आसामी। हालांकि, गार्गी देवी के मामले (5) में माननीय न्यायाधीश द्वारा एक अलग दृष्टिकोण अपनाया गया था जहां अनुबंधित किरायेदारी की समाप्ति की सूचना की अनुपस्थिति की दलील पर विचार करने के लिए अपने लिखित बयान में संशोधन के लिए किरायेदार के आवेदन को अस्वीकार करने के अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि संशोधन के लिए उसके आवेदन के अंतिम चरण के बावजूद किरायेदार की ओर से कोई छूट नहीं दी गई थी।सवराज पाल*(2)*[2] में डिवीजन बेंच के फैसले और भैया राम के मामले (1) में पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा रखा गया था। इस मामले में याचिकाकर्ता श्री जैन के विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि अनुबंध किरायेदारी को पहले ही जब्त कर लिया गया था जब किराए का भुगतान न करने के आधार पर वर्तमान निष्कासन आवेदन प्रतिवादी-किरायेदार के खिलाफ दायर किया गया था और निष्कासन का कोई नोटिस आवश्यक नहीं था क्योंकि प्रतिवादी केवल एक वैधानिक किरायेदार के रूप में परिसर के कब्जे में था।एक निश्चित समझौते पर भरोसा

---

[2] (2)आई.एल.आर. (1969)1 Pb. & Hr. 440-1968 P.L.R. 720.

(3) 1968 पी.एल.आर.

(4) 1969 रेंट कंट्रोल जर्नल 139.

(5) 1969 करी एल.जे. 926.

रखा गया जो उसी वर्ष के दौरान पहले दायर किए गए इसी तरह के एक निष्कासन आवेदन में पार्टियों के बीच हुआ था।

3. प्रदर्शनी पी.डब्ल्यू. 5/ए, 29 अप्रैल, 1966 के समझौते के विलेख की एक प्रति है। पिछला निष्कासन आवेदन जिसमें यह समझौता किया गया था, 29 मार्च, 1966 को दायर किया गया था और निष्कासन का एक आधार किराए का भुगतान न करना था। पार्टियों ने सहमति व्यक्त की कि 29 अप्रैल,1966 तक बकाया राशि 1,000 रुपये थी। प्रतिवादी किरायेदार द्वारा समझौते की तारीख (29 अप्रैल, 1966) को याचिकाकर्ता मकान मालिक को 600 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था, जिसमें 400 रुपये शेष थे। इस बात पर सहमति हुई कि किरायेदार इस शेष राशि का भुगतान 29 मई, 1966 को या उससे पहले एक महीने के भीतर करेगा। यदि इस तारीख तक शेष राशि के भुगतान में चूक हुई थी, तो किरायेदार ने मकान मालिक को परिसर के कब्जे में रखने का बीड़ा उठाया। इस समझौते के आधार पर पारित अंतिम आदेश साबित नहीं हुआ है, लेकिन बार में यह कहा गया था कि निष्कासन आवेदन 29 अप्रैल, 1966 को खारिज कर दिया गया था और उस मामले में मकान मालिक को निर्धारित तिथि तक बकाया राशि के भुगतान में चूक के मामले में किरायेदार की बेदखली के लिए निष्पादन करने का अधिकार नहीं दिया गया था।

4. यह पार्टियों का सामान्य आधार है कि प्रतिवादी किरायेदार इस समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा। इसलिए किराए का भुगतान न करने के आधार पर वर्तमान निष्कासन आवेदन 2 दिसंबर, 1966 को दायर किया गया था।मूल किराया नोट में 6 महीने की अवधि के लिए अग्रिम किराए का दावा करने की शर्त पर ध्यान दिलाया गया था और इस किराया नोट के नियमों और शर्तों के उल्लंघन का आरोप निष्कासन आवेदन के पैराग्राफ 2 में लगाया गया है। निष्कासन आवेदन में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि किरायेदार द्वारा 29 मई, 1966 को किरायेदारी को जब्त कर लिया गया था, क्योंकि किरायेदार ने समझौता विलेख, प्रदर्शनी पीडब्ल्यू 5/ए के अनुसार बकाया राशि के भुगतान ®में चूक की थी, या मकान मालिक ने ऐसी किसी जब्ती के आधार पर पट्टे का निर्धारण किया था। 15 मई, 1960 का किराया नोट, प्रदर्शनी पी 1, शुरू में 6 महीने की अवधि के लिए था, लेकिन किरायेदार को उस प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद पुरानी शर्तों पर कब्जा जारी रखने का विकल्प दिया गया था। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इस निष्कासन आवेदन को इस तरह से तैयार नहीं किया गया था कि वह हाल ही में किए गए बदलावों के अनुरूप हो। निष्कासन आवेदन के पैरा 4 के अनुसार कार्रवाई का कारण मकान मालिक को 29 अप्रैल, 1966 से प्राप्त हुआ था न कि 29 मई, 1966 को, जो चूक की तारीख थी, जिसके कारण किरायेदारी को कथित रूप से जब्त कर लिया गया था, जिसे अब निष्कासन आवेदन दाखिल करने से पहले संविदा किरायेदारी की समाप्ति के लिए आधार के रूप में स्थापित किया गया है।

5. भैया राम के मामले (1) में पूर्ण पीठ के फैसले के अनुसार, संपत्ति अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में नोटिस देने का सवाल केवल तभी उठता है जब उस धारा के प्रावधान या सिद्धांत लागू होते हैं या संविदा किरायेदारी या किरायेदारी जिसे धारा 116 के तहत अस्तित्व में माना जाता है वह मासिक है या ऐसी मासिक किरायेदारी अस्तित्व में है और समय की बर्बादी या जब्ती से या अधिनियम की धारा 106 के उचित और न्यायसंगत सिद्धांतों के तहत उचित नोटिस द्वारा निर्धारित होने से पहले ही समाप्त नहीं हुई है, जिसे उस अधिनियम की धारा 1 के तहत किसी भी अधिसूचना द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य में विस्तारित नहीं किया

गया है।जहां अनुबंधित किरायेदारी पहले ही समाप्त हो चुकी है और किरायेदार को वैधानिक किरायेदारी के तहत कब्जा जारी है, जो उसे कानून द्वारा प्रदत्त अपरिवर्तनीयता का दर्जा देता है, तो संपत्ति अधिनियम की धारा 106 के तहत कोई नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

6. ऐसे में सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता-मकान मालिक द्वारा वर्तमान निष्कासन आवेदन दायर करने से पहले अनुबंध किरायेदारी का निर्धारण जब्ती द्वारा किया गया था या अन्यथा। उनके वकील श्री जैन द्वारा संपत्ति अधिनियम की धारा 111 के खंड (बी) और (जी) पर भरोसा किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि पहले के निष्कासन आवेदन में समझौते के अनुसार यह सहमति हुई थी कि किरायेदार द्वारा किराए की शेष राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में जब तक कि मकान मालिक ने पट्टेदार को लिखित रूप में नोटिस देकर या अपनी ओर से ऐसे इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए कोई अन्य प्रत्यक्ष कार्य करके ज़ब्ती लागू करने का अपना इरादा नहीं दिखाया था। नामदेव लोकमन लोधी बनाम नर्मदाबाई और अन्य (6)[3]के आधार पर यचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस पर दलील दी थी कि संपत्ति अधिनियम की धारा 111 (जी) का बाद का हिस्सा, जहां तक मकान मालिक के लिए पट्टे का निर्धारण करने के अपने इरादे के बारे में पट्टेदार को लिखित में नोटिस देना आवश्यक बनाता है, न्याय, समानता और अच्छे विवेक के विचारों के अनुरूप नहीं है और इसलिए संपत्ति अधिनियम का यह प्रावधान पंजाब में लागू नहीं किया जाए जहां कुछ धाराओं को छोड़कर इस अधिनियम को विशेष रूप से विस्तारित या लागू नहीं किया गया है। इस खंड को 1929 के अधिनियम 20 की धारा 57 द्वारा संशोधित किया गया था और लिखित में नोटिस प्रदान करने वाले अंतिम वाक्यांश को उन शब्दों के लिए प्रतिस्थापित किया गया था जिनके लिए आवश्यक था कि मकान मालिक को पट्टे का निर्धारण करने के अपने स्पष्ट इरादे को दिखाते हुए कुछ कार्य करना चाहिए। नामदेव के मामले (6) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह माना गया था कि नोटिस की सेवा के संबंध में लिखित शर्त न्याय, समानता और अच्छे विवेक के विचारों के अनुरूप नहीं थी, लेकिन पुरानी शर्त जिसमें यह आवश्यक था कि मकान मालिक को पट्टे का निर्धारण करने के अपने स्पष्ट इरादे को दिखाने के लिए कुछ करना चाहिए, स्पष्ट कारणों से काफी उचित और न्यायसंगत पाया गया। जब्ती या अस्वीकरण को लागू करने के लिए मकान मालिक के प्रिय या स्पष्ट इरादे को दर्शाने वाले किसी भी कार्य के अभाव में मकान मालिक द्वारा पट्टे की समाप्ति की छूट हो सकती है और पट्टे को निर्वाह के रूप में मानने के उसके इरादे से अनुमान लगाया जा सकता है। 1929 में किए गए संशोधनों द्वारा, मकान मालिक की ओर से यह अतिरंजित कार्य विशेष रूप से लिखित में नोटिस का आकार लेने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट और पूर्ण पीठ के कुछ हालिया फैसले हैं जो दिखाते हैं कि संपत्ति अधिनियम के एक वैधानिक प्रावधान में न्याय, समानता और अच्छे विवेक के विचारों के साथ कुछ भी असंगत नहीं था, जिसमें पट्टेदार के पट्टे का निर्धारण करने के इरादे पर लिखित में नोटिस की सेवा की आवश्यकता होती है। राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान बनाम सीतापुर, नगरपालिका बोर्ड और अन्य (7)[4] के अनुसार, यह देखा गया कि संपत्ति अधिनियम की धारा 111 (जी) में सन्निहित सिद्धांत उन क्षेत्रों में किरायेदारों पर समान रूप से लागू होते हैं जिन पर उक्त

---

[3] (6) ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 228.

[4](7)ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1923.

(8) ए.आई.आर. 1919 पी.सी. 1

अधिनियम लागू नहीं होता है क्योंकि ये प्रावधान न्याय, समानता और अच्छे विवेक के विचारों के अनुरूप थे। खंड (छ) के पुराने या संशोधित भागों में कोई अंतर नहीं किया गया था और जयपोर के महाराजा बनाम भारत रुक्मिणी पट्टामहा-देवी (8) जिस पर नाम देव के मामले (6) में भरोसा किया गया था, उस पर राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान के मामले (7) में भी सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा किया था । संपत्ति अधिनियम की धारा 106 के तहत नोटिस की सेवा के संबंध में प्रावधानों को भी भैया राम के मामले (1) में पूर्ण पीठ द्वारा उचित और न्यायसंगत पाया गया भले ही इस बात पर दो राय हो सकती है कि उस धारा द्वारा निर्धारित 15 दिनों की अवधि पर्याप्त थी या नहीं। धारा 111 (जी) के तहत मकान मालिक के इरादे के नोटिस की सेवा के संबंध में प्रावधान नोटिस की कोई मनमानी अवधि निर्धारित नहीं करता है और इसलिए, इस प्रावधान को अधिक उचित और न्यायसंगत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये निर्णय स्पष्ट करते हैं कि न्याय, समानता या अच्छे विवेक की धारणाएं केवल सापेक्ष हैं और समय-समय पर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर या परिस्थितियों या वातावरण के एक सेट से दूसरे में बदल सकती हैं। किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता-मकान मालिक द्वारा तैयार किया गया निष्कासन आवेदन जब्ती द्वारा पट्टे की कथित समाप्ति पर आधारित नहीं है क्योंकि निर्धारित तिथि तक बकाया राशि के भुगतान में किरायेदार की चूक के कारण और बेदखली आवेदन में दिए गए कथन स्पष्ट रूप से मकान मालिक की ओर से मूल संविदात्मक पट्टे को अस्तित्व में मानने के इरादे को दर्शाते हैं। इसलिए, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ज़ब्ती को लागू करने के मकान मालिक के इरादे की छूट दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप संविदात्मक किरायेदारी की कथित समाप्ति हुई है और संपत्ति अधिनियम की धाराएं 106, 111 (जी) और 112 स्पष्ट रूप से लागू हैं क्योंकि वे कानून के उचित और न्यायसंगत सिद्धांतों को अपनाता है।

7. प्रतिवादी-किरायेदार द्वारा लिखित बयान जनवरी, 1967 में दायर किया गया था, जब यह आमतौर पर समझा जाता था कि संपत्ति अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में किरायेदारी की समाप्ति की सूचना आवश्यक नहीं थी। याचिकाकर्ता-मकान मालिक द्वारा दायर निष्कासन आवेदन में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि किरायेदार को ऐसा कोई नोटिस दिया गया था और इसलिए किरायेदार के लिए याचिका को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए, किरायेदार की ओर से कोई जानबूझकर और सचेत कार्य नहीं किया गया था ताकि छूट दी जा सके और भैया राम (1) और स्वराज पाल (2) के मामलों में पीठ के फैसलों को ध्यान में रखते हुए , अपीलीय प्राधिकारी द्वारा नोटिस की कमी की दलील को उठाने की अनुमति दी गई थी भले ही यह कहा जा सके कि यह कार्यवाही के देर से चरण में था।

8. रिमांड से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि यह किसी का मामला नहीं था कि याचिकाकर्ता-मकान मालिक द्वारा वर्तमान निष्कासन आवेदन दायर करने से पहले प्रतिवादी-किरायेदार को किरायेदारी की समाप्ति का नोटिस दिया गया था।

9. इसलिए, मैं पुनरीक्षण याचिका को खारिज की जाती है लेकिन पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।[5]

---

[5]एन.के.एस

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा